विनिर्माण में सफलता के लिए एफडीआई सीपी चंद्रशेखर, जयति घोष

द हिंदू

पेपर-III (अर्थव्यवस्था)

वर्तमान एनडीए सरकार के तहत औद्योगिक नीति में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण 'नवाचार' उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना है। यह घरेलू उत्पादन के आधार पर वृद्धिशील बिक्री के 4-6 प्रतिशत का प्रोत्साहन भुगतान या सब्सिडी प्रदान करता है। ध्यान सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर है, क्योंकि कोई घरेलू मूल्य संवर्धन या निर्यात बिक्री आवश्यकताएं निर्धारित नहीं हैं।

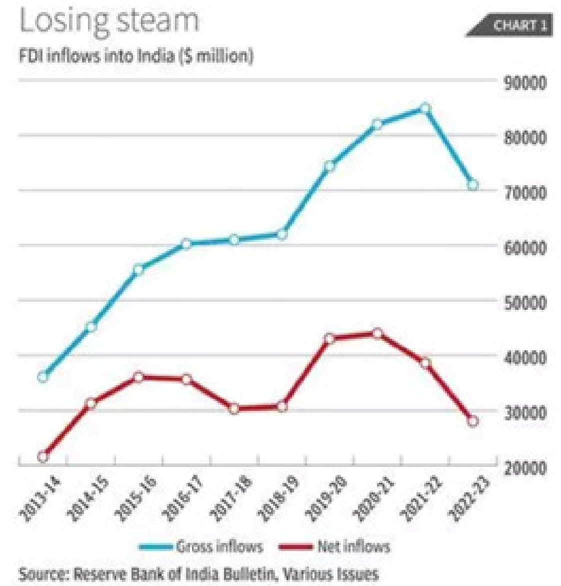

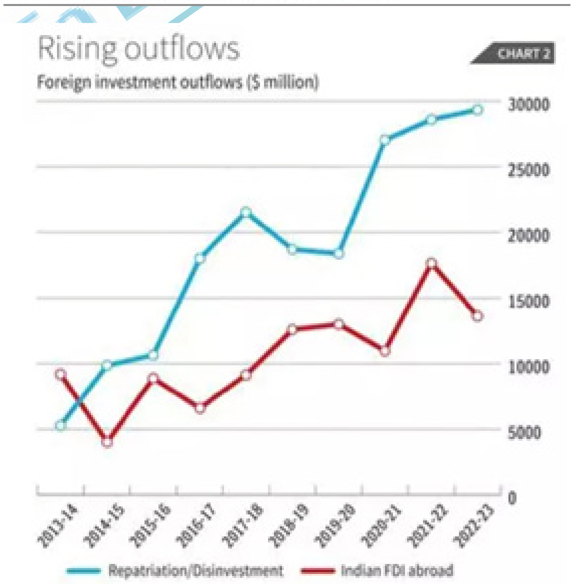

जैसा कि रघुराम राजन और उनके सहयोगी ने इंगित किया है, उदाहरण के तौर पर आईफोन उत्पादन का उपयोग करते हुए, यह विदेशी फर्मों को उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए घटकों और उपकरणों को आयात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। जब तक निवेश और उत्पादन में वृद्धि होती है, तब तक सरकार के परिप्रेक्ष्य में यह ठीक प्रतीत होता है। इसलिए, अप्रैल 2020 में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र तक सीमित लॉन्च के बाद, इस योजना को 14 बहुत विविध डोमेन को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया है।

हालांकि यह घरेलू इंडस्ट्री के लिए भी खुला है, लेकिन सच यही है कि हर तरह से यह योजना विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लक्षित है। लेकिन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साक्ष्य इस बात के बहुत कम संकेत दिखाते हैं कि इस योजना से कोई फर्क पड़ा है। बल्कि, जैसा कि चार्ट 1 दिखाता है, वित्तीय वर्ष 2021 के बाद से, 2021-22 में सकल एफडीआई प्रवाह में कमी आई है, जो कि कोविड वर्ष 2020-21 में 10.2 प्रतिशत की तुलना में केवल 3.5 प्रतिशत बढ़ गया है। 2022-23 में, सकल अंतर्वाह 16 प्रतिशत और गिर गया। इसका मतलब यह नहीं है कि पीएलआई योजना अभी काम कर रही है।

यहां तक कि 2021-22 में मामूली वृद्धि भी संभवतः कोविड के बाद वैश्विक बड़ी कंपनियों द्वारा भारतीय समूहों में शेयरों के अधिग्रहण से प्रभावित थी, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में अमेजॉन द्वारा +20 बिलियन की हिस्सेदारी की खरीद, जो अपने भारी कर्ज

को कम करने के लिए इक्विटी पूंजी जुटाने की मांग कर रही थी। शेयर अधिग्रहण मार्ग के माध्यम से एफडीआई प्रवाह 2020-21 में 7 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 14.1 बिलियन डॉलर हो गया, जो 2022-23 में 8.2 बिलियन डॉलर पर वापस आ गया। इस तरह के प्रवाह नई विनिर्माण क्षमता के निर्माण में बहुत कम योगदान देते हैं।

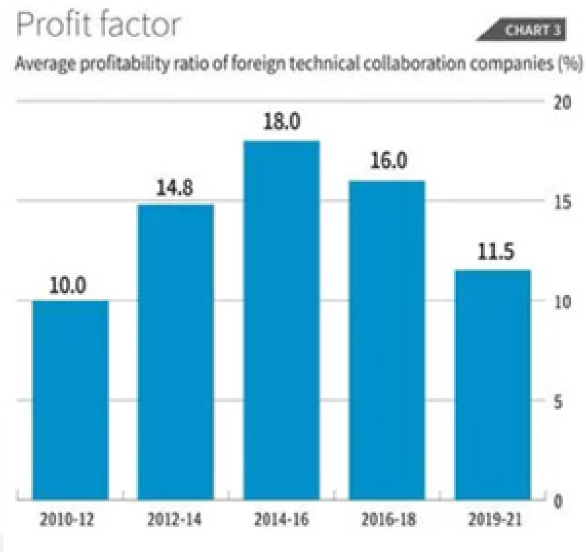

Note: Profitability is measured as gross profit to capital employed
Source: RBI Survey on Foreign Collaboration in Indian Industry: 2019-2021

हालाँकि, सरकार इस योजना पर दांव लगाती दिख रही है और अपने विश्वास में दृढ़ है कि इसका प्रभाव एक अंतराल के बाद जरूर दिखाई देगा। 2023 में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि यह योजना अगले पांच वर्षों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का निवेश देगी। लेकिन अभी तक, इस तरह के आशावाद का कोई कारण नहीं प्रतीत होता है।

शुद्ध एफडीआई प्रवाह

चिंता का एक अन्य स्रोत यह है कि शुद्ध एफडीआई प्रवाह, प्रत्यावर्तित निवेश और विदेशों में भारतीय निवेश को ध्यान में रखते हुए, कमोबेश स्थिर रहा है और 2020-21 से गिर ही रहा है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि जब सकल अंतर्वाह बढ़ रहा था तब भी बहिर्प्रवाह तेजी से बढ़ रहा था।

चार्ट 2 विदेशों में भारतीय एफडीआई के कारण और मौजूदा विदेशी निवेशकों द्वारा संपत्ति के प्रत्यावर्तन या विनिवेश के कारण सकल बहिर्वाह को अलग करता है। जबकि निवासियों द्वारा विदेशों में निवेश में 2014-2017 में औसतन +6.5 बिलियन से 2017-20 में +11.6 बिलियन और 2020-23 में +14.1 बिलियन से कुछ वृद्धि हुई है। जबकि इसी समयकाल में विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यावर्तन/विनिवेश के आंकड़े 2014-2017 में +12.8 बिलियन थे, 2017-20 में +19.5 बिलियन और 2020-23 में +28.3 बिलियन हैं।

स्पष्ट रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि नए निवेश प्रवाह के आने के बजाय विदेशी निवेशकों के बाहर निकलने में तेजी आई है।

सकल, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से शुद्ध, एफडीआई प्रवाह में गिरावट की व्याख्या करने वाला एक अन्य कारक लाभ में गिरावट की प्रवृत्ति है, जिसे नियोजित पूंजी के लिए सकल लाभ के अनुपात से मापा जाता है। यह उन फर्मों पर सर्वेक्षण में बताया गया है जिन्होंने विदेशी तकनीकी सहयोग में प्रवेश किया है और जो या तो विदेशी सहायक कंपनियां हैं या महत्वपूर्ण विदेशी हिस्सेदारी वाले उद्यम हैं।

जैसा कि चार्ट 3 दिखाता है, औसत लाभ अनुपात, जो 2010-12 के दौरान 10 प्रतिशत से बढ़कर 2012-14 में 14.8 प्रतिशत और 2014-16 में 18 प्रतिशत हो गया था वही लाभ 2016-18 में 16 प्रतिशत और 2019-21 में 11.5 प्रतिशत से अधिक तक गिर गया। इनमें आ रही यह कमी महामारी के प्रभावों को दर्शाता है, लेकिन लाभप्रदता 2019-20 में भी 14.6 प्रतिशत कम रही।

DELHI (H.O.): 632, Ground Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi-9 | For any Query : 9654349902

हम इस प्रवृत्ति को बहुत अधिक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यह फर्मों द्वारा रिपोर्ट किए गए मुनाफे पर आधारित है, जो कि अन्य कारकों से प्रेरित हो सकता है, जैसे मूल्य निर्धारण में वृद्धि का सहारा लेना, लेकिन ट्रेंड्स एक वास्तविक गिरावट की ओर इशारा करती है जिसे वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन द्वारा आसानी से बेअसर नहीं किया जा सकता है।प्रत्यावर्तन/विनिवेश मार्ग के माध्यम से विदेशी निवेश का बढ़ा हुआ निकास भी हाल के दिनों में एफडीआई की प्रकृति की बात करता है।

वैचारिक रूप से, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश के विपरीत, दीर्घकालिक ब्याज से प्रेरित निवेश माना जाता है जो कि निश्चित पूंजीगत व्यय से काफी हद तक संबद्ध है।

पोर्टफोलियो की अस्थिरता

इसलिए, इक्विटी में पोर्टफोलियो निवेश की तुलना में इसे बहुत कम 'फुटलूज' माना जाता है। हालांकि, एफडीआई की सांख्यिकीय परिभाषा, एक एकल विदेशी स्रोत से कोई भी निवेश है जो एक घरेलू फर्म में 10 प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी प्राप्त करता है। यह ज्ञात है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक व्यक्तिगत भारतीय फर्मों में 10 प्रतिशत से अधिक इक्विटी खरीदने के लिए अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की तलाश कर रहे हैं।

इस तरह के निवेश, इसलिए, पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा परिव्यय होते हैं, जो मुनाफावसूली करते हैं और अपेक्षाकृत कम अवधि के भीतर बाहर निकल जाते हैं। प्रत्यावर्तन/विनिवेश के कारण बहिर्वाह में वृद्धि संभवत: एफडीआई के रूप में गिने जाने वाले ऐसे पोर्टफोलियो निवेशों के हिस्से में वृद्धि की ओर इशारा करती है।

समय के साथ निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाहों के आंकड़े (चार्ट 4) संकेत देते हैं कि प्रवाहों में इस आंशिक अस्थिरता के परिण ामस्वरूप औसतन स्थिरता आई है। शुद्ध एफडीआई प्रवाह 2014-17 के दौरान औसतन +34.3 बिलियन, 2017-20 में +34.7 बिलियन और 2020-23 में +36.9 बिलियन रहा।

यह भुगतान संतुलन के दृष्टिकोण से समस्याग्रस्त है, क्योंकि सापेक्ष स्थिर और बढ़ते एफडीआई प्रवाह को पोर्टफोलियो प्रवाह में अस्थिरता की भरपाई करके कुल शुद्ध प्रवाह को बढ़ाने के रूप में देखा गया था। निवल प्रवाह वास्तव में पिछले एक दशक में अत्यधिक अस्थिर रहा है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2021-22 और 2022-23 में, पोर्टफोलियो निवेश का शुद्ध बहिर्वाह काफी नकारात्मक हो गया है, जो शुद्ध एफडीआई प्रवाह में कमी तथा देश में कुल शुद्ध निवेश प्रवाह में कमी के संयुक्त रूप में परिणत हुआ है।

यह सच है कि प्रेषण और सेवाओं के निर्यात राजस्व के बड़े अंतर्वाह के कारण एक छोटा चालू खाता घाटा, भुगतान संतुलन को बनाए रखने के लिए पूंजी प्रवाह पर भारत की निर्भरताओं को कम करता है। बहरहाल, यह चिंता का विषय बन सकता है।

भारत सरकार स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के नाम पर अनुत्पादक तरीकों से विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के बजाय इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर वास्तव में कुछ अच्छा कर सकती है।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक आउटपुट उन्मुख योजना है।
2. इस योजना को 14 विविध डोमेन को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2

(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to Production Linked Incentive (PLI) scheme:

1. It is an output oriented scheme.
2. The scheme has been expanded to cover 14 diverse domains.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : c

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : भारत के विनिर्माण क्षेत्र के विकास के संदर्भ में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। (250 शब्द)

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- उत्तर की शुरुआत में भारत के विनिर्माण क्षेत्र की चर्चा करें।
- उत्तर के अगले भाग में भारत के विनिर्माण क्षेत्र के विकास के संदर्भ में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की सकारात्मक भूमिका की चर्चा करें।
- आगे भाग में विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में इस योजना से जुड़ी चिंताओं की चर्चा करें।
- अंत में आगे की राह दिखाते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।